एम.एल. सिंघल, जे

हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और अन्य, याचिकाकर्ता

बनाम

एम/एस कैबिस शाइन्स प्राइवेट लिमिटेड,प्रतिवादी

1999 के सी। आर। नंबर 3213

4 अक्टूबर, 2001

राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951-S.29-कोड ऑफ सिविल प्रक्रिया, 1908-0.39 आरएलएस। 1 और 2-विफलता ऋण राशि-कॉर्पोरेशन का भुगतान करने के लिए ऑर्डर करने के लिए ऑर्डर करने के लिए औद्योगिक इकाई-ट्रायल कोर्ट पर कब्जा करने के लिए निगम-1st अपीलीय अदालत के खिलाफ निषेधाज्ञा देने के लिए अपीलीय अदालत को एक मात्र तकनीकी पर अपील को खारिज कर देता है। अपील-आयोजित फाइल करें, हाँ, निगम के ब्याज को प्रक्रियात्मक अनियमितता के कारण पीड़ित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, यदि कोई भी हाविंग डिफ़ॉल्ट राशि के पुनर्निर्धारण के बावजूद ऋण राशि को चुकाने में विफल रहा, तो निगम के निर्णय को यूनिट के कब्जे में लेने का निर्णय वादी के पक्ष में दी गई अस्थायी निषेधाज्ञा को खाली करते हुए वादी ने न तो मनमानी और न ही अन्यायपूर्ण याचिका की अनुमति दी।

आयोजित, कि हरियाणा वित्तीय निगम ऋण के अनुसार रु 90 लाख 20.3.93 पर दिया गया था। इसे 29 त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना था। वादी के अनुरोध पर, डिफ़ॉल्ट राशि को बकाया राशि के पुनर्निर्धारण के अनुसार भुगतान करने की अनुमति दी गई थी। वादी, पुनर्निर्धारित राशि के भुगतान में चूक की। रुपये की कुल राशि में से 174.88 लाख, देय ऋण समझौते के पुनर्भुगतान शेड्यूल के अनुसार, वादी ने केवल रु। 55.80 लाख और शेष राशि 19.9.97 से आगे ब्याज के कारण थी। वादी की इकाई को संभालने के लिए हरियाणा वित्तीय निगम का निर्णय, इस प्रकार, असमान या अन्यायपूर्ण नहीं था।

(पैरा 17)

याचिकाकर्ताओं के

लिए, कमल साहगल एडवोकेट के साथ सूर्या कांत अधिवक्ता

एच। एल। सिबल, सीनियर वकील रीता कोहली के साथ, प्रतिवादी के लिए वकील

निर्णय

मंचित सिंघल। जे।

(1) 23 दिसंबर, **1997** के अतिरिक्त सिविल जज, सीनियर डिवीजन के आदेश के आदेश, हिसार ने एम/एस काबिस शाइन्स, प्रा। के आवेदन की अनुमति दी। लिमिटेड, भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक कंपनी, हरियाणा फिनैशियल कॉर्पोरेशन को अपनी कारखाने इकाई पर कब्जा करने से रोकती है। अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के **23** दिसंबर, **1997** को इस आदेश से संतुष्ट नहीं, हिसार हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अपील में गए। **27** फरवरी, **1999** को वीडब्ल्यू ऑर्डर दिनांकित जिला न्यायाधीश हिसार ने अपील को खारिज कर दिया। अभी भी संतुष्ट नहीं है, हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इस अदालत में संशोधन में आ गया है।

(**2**) इस आदेश के माध्यम से, सिविल संशोधन संख्या ३२०२, ३२१३, ३२१४, ३२१४, ३२१५ और ३२१६ १ ९९९ के रूप में निपटाया जाएगा क्योंकि कानून का एक ही प्रश्न और तथ्य इन सभी संशोधनों में शामिल है।

तथ्य:

(**3**) एम/एस काबिस शाइन प्रा। भारतीय कंपनी अधिनियम, **1956** के तहत पंजीकृत कंपनी लिमिटेड ने रु। का ऋण प्राप्त किया। **14.12.93** पर **85.37** लाख जो **29** किस्तों में चुकाया जाना था। रु। हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को **16.12.97** तक **39.40** लाख का भुगतान किया गया था। रु। **6** लाख **12.12.97** पर बनाया गया था। वादी के अनुरोध पर, डिफ़ॉल्ट राशि को पुनर्निर्धारण लेटर दिनांक **26.7.96** के अनुसार भुगतान करने की

अनुमति दी गई थी। फिर भी, वादी डिफ़ॉल्ट राशि का भुगतान करने में विफल रहा। रुपये की कुल राशि में से। **132.93** लाख, केवल रुपये का भुगतान। **39.40** लाख **16.12.97** तक बनाया गया था। रु। **6** लाख **12.12.97** पर बनाया गया था। शेष राशि **1.12.97** से आगे ब्याज के कारण थी। जब वादी भुगतान करने में विफल रहा, तो हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन द्वारा राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, **1951** (संक्षेप में अधिनियम में) की धारा **29** के तहत आदेश पारित किया गया था कि इसकी औद्योगिक इकाई के डोसेशन को लिया जाना चाहिए और इसे बिक्री के लिए रखा जाए।

वादी ने **28** नवंबर, **1997** को लिए गए अपने फैसले के आधार पर हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को अपनी औद्योगिक इकाई पर कब्जा करने से रोकते हुए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया। यह आरोप लगाया गया था कि उक्त निर्णय अवैध है, बिना अधिकार क्षेत्र, माला फाइड, के बिना। राजनीतिक विचारों के आधार पर, कानून के विपरीत, शून्य एबी-इनिटियो और नॉनस्ट। यह आगे आरोप लगाया गया था कि वादी तैयार है और आसान किस्त में शेष राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है। सुविधा का संतुलन इस प्रकार इसके पक्ष में है। इसके पक्ष में एक प्रथम दृष्टया मामला भी है। वादी के साथ, वादी ने अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुदान के लिए एक आवेदन किया, जिसमें प्रतिवादी हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेटिपॉन को अपनी औद्योगिक इकाई पर कब्जा करने से रोकते हुए आरोप लगाया गया कि यह तैयार है और आसान किस्त में शेष राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है। यदि अस्थायी निषेधाज्ञा इसे प्रदान नहीं की जाती है, तो यह अपूरणीय चोट से पीड़ित होगी क्योंकि यह पहले से ही **100** से अधिक श्रमिकों को नियोजित कर चुका है। वे अपनी नौकरी खो देंगे। औद्योगिक क्षेत्र में मंदी है।

(**4**) प्रतिवादी हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुदान का विरोध किया, जिसमें कहा गया था कि वादी ने रुपये का ऋण प्राप्त किया है। **14** दिसंबर, **1993** को **85.37** लाख जो **29** किस्तों में चुकाया जाना था। वादी ने केवल रु। **39.40** लाख **16** दिसंबर **1997** तक। रुपये की राशि। **12** दिसंबर **1997** को **6** लाख का भुगतान किया गया था। किस्तों का भुगतान करने में वादी की विफलता पर 'शेष राशि को पुनर्निर्धारण के अनुसार भुगतान करने की अनुमति दी गई थी। वादी को पुनर्निर्धारित के रूप में राशि के भुगतान में डिफ़ॉल्ट किया गया। शेष राशि **1** दिसंबर **1997** से आगे की रुचि के साथ वादी के खिलाफ है। हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने अधिनियम की धारा **29** के तहत अपनी औद्योगिक इकाई पर कब्जा करने का फैसला किया और इसे बिक्री में डाल दिया। अपनी औद्योगिक इकाई पर कब्जा करने का इसका निर्णय पूरी तरह से वैध, न्यायसंगत और कानूनी है। वादी के पास कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है और न ही सुविधा का संतुलन इसके पक्ष में है।

(**5**) २३ दिसंबर १ ९९ (सिविल डिवीजन) के आदेश के आदेश, हिसर ने वादी को अपनी औद्योगिक इकाई पर कब्जा करने से प्रतिवादी हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को रोकने के लिए वादी को अस्थायी निषेधाज्ञा की अनुमति दी। सीखा जिला न्यायाधीश ने **27** फरवरी **1999** को दिनांकित प्रतिवादी की अपील के आदेश के आदेश को खारिज कर दिया।

(6) अभी भी संतुष्ट नहीं है, प्रतिवादी हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इस अदालत में संशोधन में आ गया है। याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि सीखा जिला न्यायाधीश ने एक छोटी सी जमीन पर अपील को खारिज कर दिया था कि अपील दायर करने का निर्णय एक सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं लिया गया था और हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के शाखा प्रबंधक, हिसार को अधिकृत नहीं किया गया था/ अपील दायर करने के लिए सक्षम। यह प्रस्तुत किया गया था कि अपील दायर करने का निर्णय हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक द्वारा लिया गया था और इस निर्णय को शाखा प्रबंधक को अनुलग्नक पी -1 के माध्यम से भी दिया गया था और प्रबंध निदेशक द्वारा नोटिंग प्राधिकरण पर आदेश दिया गया है। अपील दायर करने के लिए शाखा प्रबंधक। यह प्रस्तुत किया गया था कि यह अपील दायर करने के लिए शाखा प्रबंधक का अपना निर्णय नहीं था, लेकिन यह प्रबंध निदेशक का निर्णय था कि अपील दायर की जाए। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस मामले में, हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक ने खुद अपील दायर करने के लिए कहा था और शाखा प्रबंधक को अपने फैसले को अवगत कराया, जिससे वह अपील दायर करने के लिए अधिकृत हो गया। यह प्रस्तुत किया गया था कि अन्यथा केवल एक तकनीकीता पर भी कि अपील एक सक्षम व्यक्ति द्वारा दायर की गई थी, इसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए था। यह मानते हुए कि अपीलीय अदालत ने महसूस किया कि अपील को एक सक्षम व्यक्ति द्वारा दायर नहीं किया गया था, यहां तक कि यह भी, योग्यता पर अपील का फैसला करना चाहिए था। इस सबमिशन के समर्थन में, उन्होंने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम नरेश कुमार और अन्य (1) पर मेरा ध्यान आकर्षित किया, जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निम्नानुसार देखा:-

"ऐसे मामलों में जहां बैंक जैसे सार्वजनिक निगम की ओर से सूट स्थापित या बचाव किया जाता है; सार्वजनिक हित को केवल एक तकनीकी पर हराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। प्रक्रियात्मक दोष जो मामले की जड़ में नहीं जाते हैं, उन्हें हारने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एक उचित कारण है। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत, अदालतों में थीयर पर्याप्त शक्ति है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अन्याय किसी भी पार्टी के लिए नहीं किया जाता है, जिसके पास सिर्फ एक मामला है। जहां तक संभव हो एक ठोस अधिकार को हराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एक प्रक्रियात्मक अनियमितता का खाता जो इलाज योग्य है।

---

(7) यह प्रस्तुत किया गया था कि सीखा जिला न्यायाधीश द्वारा सीखा जिला न्यायाधीश द्वारा प्रक्रिया की वेदी पर बलिदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी, जब सीखा जिला न्यायाधीश ने खुद देखा है कि "वादी और द वादी के खिलाफ ऋण की बड़ी राशि बकाया है और वादी ने सूट दाखिल होने के बाद भी एक भी पाई का भुगतान नहीं किया है। वादी द्वारा दिए गए चेक को पहले ही वादी द्वारा वापस ले लिया गया है और डिफेंडेंट हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन निचली अदालत में उचित कानूनी कार्यवाही ले सकता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि जब सीखा जिला न्यायाधीश ने खुद महसूस किया था कि वादी के खिलाफ भारी मात्रा में ऋण था, जो वादी बकाया राशि को पुनर्निर्धारित करने के बावजूद चुकाने में विफल रहा था, तो जिला न्यायाधीश को मेरिट पर अपील का फैसला करना चाहिए था और क्या किया जाना चाहिए था या नहीं। वादी के पास एक प्रथम दृष्टया मामला था और आगे क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में था और क्या वादी को अपूरणीय चोट लगी होगी यदि निषेधाज्ञा नहीं दी गई थी या क्या प्रतिवादी को चोट लगी थी, अगर निषेधाज्ञा दी गई थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि सीखा जिला न्यायाधीश को केवल तकनीकी पर प्रतिवादी को ओवरबोर्ड नहीं फेंकना चाहिए था।

अधिनियम की धारा 9 इस प्रकार पढ़ती है:-
"9. वित्तीय निगमों का प्रबंधन। सामान्य अधीक्षक, दिशा और प्रबंधन और वित्तीय निगम के व्यवसाय और व्यवसाय के निदेशक मंडल में निहित होंगे जो एक कार्यकारी समिति की सहायता से और एक प्रबंध निदेशक सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और उन सभी कार्यों का निर्वहन करें जिन्हें वित्तीय निगम द्वारा प्रयोग या छुट्टी दी जा सकती है। "

(9) यह प्रस्तुत किया गया था कि हरियाणा वित्तीय निगम इस प्रकार अपने निदेशक मंडल के माध्यम से कार्य करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हरियाणा वित्तीय निगम अपने निदेशक मंडल के माध्यम से निष्पादित समिति और प्रबंध निदेशक की सहायता से काम कर सकता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के निदेशक मंडल को किसी को अधिकृत करके अपील फ़ाइल करने वाला एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए था।

इस मामले में, यह प्रस्तुत किया गया था कि ऐसा कोई संकल्प नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया था कि 21 अगस्त, 1999 को, हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया था, जो इस प्रकार पढ़ता है:-

एजेंडा आइटम नं। 178.24:

स्थानीय वकीलों को संलग्न करने और वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रबंधकों को शक्तियों का प्रतिनिधिमंडल।

बोर्ड ने कानूनी कार्यवाही के संबंध में वकालतनामा और अन्य सभी ड्यूकेंट्स पर हस्ताक्षर करने के लिए शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल को मंजूरी दी और बिक्री के कामों, मोचन कामों और बेचने के लिए समझौते और किसी भी अन्य कानूनी दस्तावेज के लिए और निगम की ओर से प्रबंधकों और ऊपर के लिए और उससे अधिक समय तक हस्ताक्षर किए। कार्यालय के साथ -साथ शाखाओं में भी।

2. इसके अलावा, बोर्ड ने उन मामलों में अपने पूर्व-पोस्ट-फैक्टो अनुमोदन को भी स्वीकार कर लिया, जहां अधिवक्ताओं को पहले से ही लगे हुए थे और सादे, लिखित बयान और वकालतनामा को उपरोक्त स्तर के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था।

(10) यह प्रस्तुत किया गया था कि इस प्रकार स्थानीय वकीलों को संलग्न करने और वकालत-नामों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रबंधकों को शक्तियों का प्रतिनिधिमंडल था। इसने उन मामलों में अपने पूर्व-पोस्ट फैक्टो अनुमोदन को भी स्वीकार कर लिया, जहां अधिवक्ताओं को पहले से ही लगे हुए थे और सादे और लिखित बयान और वकालतनामास पर उपरोक्त स्तर के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के खिलाफ अपने शाखा प्रबंधक के माध्यम से मुकदमा दायर किया गया था और जब हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अपने शाखा प्रबंधक के माध्यम से सूट का बचाव कर रहा था, तो शाखा प्रबंधक अपील भी दायर कर सकता है क्योंकि अपील सूट की निरंतरता है। योग्यता के आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया था कि वादी के खिलाफ भारी मात्रा में ऋण बकाया था, जिसे वादी ने पहले के पुनर्भुगतान अनुसूची के पुनर्निर्धारण की सुविधा के अनुदान के बावजूद चुकाने में विफल रहा था। यह प्रस्तुत किया गया था कि हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के साथ कोई अन्य विकल्प नहीं था, लेकिन इस अधिनियम की धारा 29 के तहत एक निर्णय लेने के लिए कि इसकी औद्योगिक इकाई को कब्जा कर लिया जाए और इसे बिक्री के

लिए रखा जाए। यह प्रस्तुत किया गया था कि हरियाणा वित्तीय निगम को लेना था यह प्रति शक्ति जब इसे पुनर्निर्धारित किए जाने के बावजूद चुकौती पाने की कोई उम्मीद नहीं थी।

(11) दूसरी ओर प्रतिवादी के लिए वकील सीखा प्रस्तुत किया गया कि अपील सीखा जिले से पहले बनाए रखने योग्य नहीं थी न्यायाधीश के रूप में यह शाखा प्रबंधक द्वारा दायर किया गया था जो नहीं था निदेशक मंडल द्वारा किसी भी प्रस्ताव के माध्यम से अधिकृत। वह थाnप्रस्तुत किया कि हरियाणा वित्तीय निगम कार्य करता है संकल्प। हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाता है निर्देशकों या प्रबंध निदेशक द्वारा उनकी कार्यकारी की मदद से। यह प्रस्तुत किया गया था कि निदेशक मंडल द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था या अपने कार्यकारी की मदद से प्रबंध निदेशक द्वारा उस अपील दायर किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि एजेंडा आइटम नंबर 178.24 को अपनाया गया 21 अगस्त, 1989 को अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा नहीं अपील के दाखिल होने के कारण शक्तियों के किसी भी प्रतिनिधिमंडल की बात करें संबंधित। यह प्रस्तुत किया गया था कि एजेंडा आइटम नंबर 178.24 कहीं नहीं कहते हैं कि शाखा प्रबंधक के पास तय करने की शक्ति होगी।

मामलों की अपीलें दायर की जाती हैं या दायर नहीं की जाती हैं। यह उस खंड को प्रस्तुत किया गया था अधिनियम का 2 (ए) "बोर्ड" को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है निदेशक मंडल वित्तीय निगम। "वित्तीय निगम" को खंड में परिभाषित किया गया है (बी) धारा 2 के रूप में एक वित्तीय निगम के रूप में स्थापित अनुभाग के तहत स्थापित 3 और इसमें एक संयुक्त वित्तीय निगम शामिल है जो अनुभाग के तहत स्थापित है 3 A. "निर्धारित" को नियमों या विनियमों द्वारा निर्धारित के रूप में परिभाषित किया गया है यह कार्य। अधिनियम की धारा 3 का कहना है कि वित्तीय

निगम है एक बॉडी कॉर्पोरेट। अधिनियम की धारा 9 का कहना है कि सामान्य अधीक्षक, दिशा और मामलों और व्यवसाय का प्रबंधन वित्तीय निगम निदेशक मंडल में निहित होगा जो, एक कार्यकारी समिति और एक प्रबंध की सहायता से निदेशक सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और सभी कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं जिसे वित्तीय निगम द्वारा प्रयोग या छुट्टी दी जा सकती है। यह प्रस्तुत किया गया था कि वित्तीय निगम का प्रबंधन निदेशक मंडल में निहित है जो की सहायता से कार्य करता है कार्यकारी समिति और प्रबंध निदेशक। निदेशक मंडल कार्यकारी समिति और प्रबंध की सहायता से निदेशक वित्तीय की सभी शक्तियों और कार्यों का निर्वहन करता है निगम। धारा 10 निदेशक मंडल का रंग देता है और धारा 15 बोर्ड के अध्यक्ष को संदर्भित करता है जो एक होना है निर्देशकों की। यह भी प्रदान किया जाता है कि एक ही व्यक्ति हो सकता है अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दोनों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया।

धारा 18 निगम की कार्यकारी समिति को संदर्भित करती है। यह है प्रबंध निदेशक को शामिल करने के लिए जो समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और धारा 18 में दिए गए अन्य निदेशक। धारा 19 निर्दिष्ट करता है कि

बोर्ड और कार्यकारी समिति ऐसे समय और स्थानों पर मिलेंगी और ऐसी प्रक्रियाओं के नियमों का पालन करेगी। यह प्रस्तुत किया गया था कि यह दर्शाता है कि बोर्ड और कार्यकारी समिति अलग -अलग संस्थाएं हैं। अधिनियम की धारा **20** कार्यकारी समिति की शक्तियों को परिभाषित करती है। यह ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामलों से निपट सकता है जिन्हें बोर्ड की सामान्य या विशेष दिशाओं के साथ सौंपा जाना चाहिए था। अधिनियम की धारा **43** ए बोर्ड द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रबंध निदेशक या वित्तीय निगम के किसी अन्य अधिकारी को विशेष आदेश द्वारा शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल के लिए प्रदान करती है, जिसे अधिनियम की धारा **21** के तहत नियुक्त किया गया है। धारा **47** राज्य सरकार को नियमों को फ्रेम करने के लिए शक्तियां देता है। धारा **48** नियम बनाने के लिए बोर्ड को शक्तियां देता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि ऐसे कोई नियम या नियम नहीं हैं जो निगम के शाखा प्रबंधक को अपील दायर करने के लिए सशक्त बनाते हैं। शाखा प्रबंधक को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है। यह प्रस्तुत किया गया था कि निदेशक मंडल द्वारा शाखा प्रबंधक द्वारा अपील दाखिल करने को अधिकृत करने वाले निदेशक मंडल द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(12) उत्कल विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अन्य में यर्सस एस. के. घोष और अन्य (2) को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार देखा:-

"हालांकि विश्वविद्यालय की तरह एक निगमित निकाय एक कानूनी इकाई है, इसमें न तो एक जीवित दिमाग है और न ही आवाज है। यह केवल एक औपचारिक संकल्प द्वारा औपचारिक तरीके से अपनी इच्छा को व्यक्त कर सकता है और इसलिए केवल ठीक से विचार किए गए प्रस्तावों द्वारा अपनी कॉर्पोरेट क्षमता में कार्य कर सकता है। और विधिवत रूप से इसके संविधान द्वारा निर्धारित तरीके से दर्ज किया गया है। यदि इसके नियमों को इस तरह के प्रस्तावों को स्थानांतरित करने और पारित करने की आवश्यकता होती है, तो इस उद्देश्य के लिए एक बैठक में पारित किया जाता है, तो बैठक में भाग लेने के हकदार निकाय के प्रत्येक सदस्य को नोटिस दिया जाना चाहिए। वह अपने विचारों में भाग ले सकता है और व्यक्त कर सकता है। अलग -अलग दिए गए व्यक्तिगत आश्वासन को एक बैठक की आश्वासन के बराबर नहीं माना जा सकता है क्योंकि निगमित निकाय उन व्यक्तियों से अलग है, जिनके लिए यह रचना की गई है। इसलिए, एक एकल को भी उचित नोटिस देने के

लिए एक चूक इन परिस्थितियों में सदस्य बैठक को अमान्य कर देगा और बदले में संकल्पों को अमान्य कर देगा जो उस पर पारित किया गया है।

(13) यह प्रस्तुत किया गया था कि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम राज्य वित्तीय निगम अधिनियम के तहत शामिल किया गया है। 1951 और इस प्रकार कानूनी गतिविधि है। इसमें न तो जीवित दिमाग है और न ही आवाज। यह केवल एक औपचारिक संकल्प द्वारा अपनी इच्छा को व्यक्त कर सकता है और इसलिए केवल अपने संविधान द्वारा निर्धारित तरीके से कार्य कर सकता है।

(14) अधिनियम की धारा १, उस प्रबंध निदेशक को बताएगी:-

(ए) xxxxx

(b) बोर्ड के रूप में ऐसे कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं, विनियमों द्वारा, सौंपा या उसे प्रतिनिधि कर सकते हैं।

(c) & (d) xxxxxxx

(15) जिला न्यायाधीश के समक्ष 28 तारीख को शुरू की गई थी जनवरी, 1998. प्रबंधकों के लिए शक्तियों का प्रतिनिधिमंडल था स्थानीय वकीलों को संलग्न करने और वकालतनमास पर हस्ताक्षर करने के लिए। 21 जनवरी को, 1989, हरियाणा फाइनिकल कॉरपोरेशन के निदेशक मंडल, चंडीगढ़ ने शाखा प्रबंधकों को शक्तियां देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कानूनी के संबंध में वकालतनमास और अन्य सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कार्यवाही और बिक्री कर्मों, मोचन कर्म और समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बेचने के लिए और किसी भी अन्य कानूनी दस्तावेज के लिए और की ओर से निगम। एक वकील को संलग्न करने की शक्ति में तय करने की शक्ति भी शामिल है। इस मामले में, अपील दायर करने का निर्णय प्रबंधन द्वारा लिया गया था हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के निदेशक और प्रबंधन से पहले निर्देशक ने यह निर्णय लिया, वहाँ ध्यान दिया गया था कि किस प्रबंधन निदेशक ने अपील दायर करने का फैसला किया। यह सीखा द्वारा प्रस्तुत किया गया था प्रतिवादी के लिए परामर्शदाता कि प्रबंध निदेशक प्रदर्शन कर सकते हैं केवल ऐसे कर्तव्यों के रूप में निदेशक मंडल, विनियमों द्वारा, सौंपता है या उसे प्रतिनिधि। यह प्रस्तुत किया गया था कि कोई नियम नहीं हैं हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन द्वारा डेलिगेशन की अनुमति दी गई प्रबंध निदेशकों को। सूट को बचाव के लिए अधिकृत किया गया था शाखा प्रबंधक। सूट की रक्षा करने के अधिकार में, प्राधिकरण अपील दायर करने के लिए, यदि कोई आदेश हरियाणा वित्तीय के खिलाफ जाता है निगम, निहित है। संकल्प होने पर आग्रह क्यों है एक क़ानून के तहत शामिल एक निगम द्वारा पारित वह अपील है हो या दायर नहीं किया जा सकता है ताकि

तुच्छ अपील दायर न हो और निगम अनावश्यक खर्च का बोझ नहीं है। इस मामले में, शाखा प्रबंधक ने सीखा अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) द्वारा पारित किया गया आदेश से छुटकारा पाने के लिए अपील दायर की गई थी।

हरियाणा वित्तीय निगम के खिलाफ हिसार। शाखा प्रबंधक ने अपने आप काम नहीं किया है। उन्हें हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक द्वारा अपील दायर करने के लिए अधिकृत किया गया है। यह मानते हुए कि शाखा प्रबंधक ने जिला न्यायाधीश, हिसार के समक्ष किसी भी अधिकार के बिना यह अपील दायर की थी, इस अपील को वापस ले लिया जा सकता है और एक विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा संचालित नई अपील की जा सकती है। यदि कोई देरी हुई होती तो निगम धारा **151** सीपीसी या निगम के साथ पढ़ी गई सीमा अधिनियम की धारा **5** के तहत देरी के लिए आवेदन कर सकता था या निगम ताजा अधिकार दायर कर सकता था और यदि ताजा अधिकार दायर किया गया था, ताजा अधिकार दायर किया गया था। यदि ताजा प्राधिकारी दाखिल करने में कोई देरी हुई थी, तो निगम धारा **151** सीपीसी के साथ पढ़ी गई सीमा अधिनियम की धारा **5** के तहत देरी के संघनन के लिए एक आवेदन दायर कर सकता है। किसी भी मामले में, इस प्रक्रियात्मक अनियमितता के कारण निगम के हित को पीड़ित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अस्थायी निषेधाज्ञा देने के दौरान ट्रायल कोर्ट के साथ जो तौला गया, वह यह था कि औद्योगिक क्षेत्र में मंदी थी और इस तरह से यह नहीं कहा जा सकता था कि वादी का इरादा ऋण की राशि को चुकाने के लिए नहीं था। यह इस कारक को ध्यान में रखते हुए था जिसे ट्रायल कोर्ट ने महसूस किया था कि निगम का निर्णय यूनिट पर कब्जा करने और इसे बिक्री के लिए रखना मनमाना था।

(**16**) यह कहने के लिए पर्याप्त है, हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के यूनिट पर कब्जा करने के लिए और इसे अधिनियम की धारा २ ९ के तहत बिक्री के लिए रखने के लिए यह निर्णय को मनमाना नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह निर्णय तब लिया गया था जब वादी विफल रहा था लोन राशि का भुगतान करें, हालांकि पुनर्निर्धारण किया गया था। वादी के पक्ष में कोई इक्विटी नहीं थी। यह **U.P** में आयोजित किया गया था। वित्तीय निगम बनाम एम/एस। जेम कैप (भारत) प्रा। लिमिटेड और अन्य (**3)** कि

"निगम एक साधारण धन ऋणदाता या एक बैंक की तरह नहीं है जो पैसे उधार देता है। यह एक उद्देश्य के साथ एक ऋणदाता है। -साथ छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने का उद्देश्य। एक ही समय में, कुछ बुनियादी तथ्यों को रखना आवश्यक है। देखें। निगम और उधारकर्ता के बीच संबंध लेनदार और देनदार का है। निगम को एक बार ऋण देने और व्यवसाय से बाहर जाने के लिए नहीं माना जाता है। यह उन्हें पुनर्प्राप्त करना भी है ताकि यह दूसरों को ताजा ऋण दे सके।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि निगम को अधिनियम के चार कोनों के भीतर और अधिनियम में अंतर्निहित वस्तु के आगे काम करना है। लेकिन इस कारक को निगम को पुनर्जीवित करने और पुनर्जीवित करने के लिए बाध्य करने की सीमा तक नहीं ले जाया जा सकता है, भले ही इसमें शामिल लागत के बावजूद हर बीमार उद्योग को पुनर्जीवित किया जाए। सार्वजनिक धन की लागत पर औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना सार्वजनिक हित की सेवा नहीं करता है; यह केवल सार्वजनिक धन को निजी खाते में स्थानांतरित करने के लिए राशि है। निगम के लिए आवश्यक निष्पक्षता को इसे ठीक करने से अक्षम करने की सीमा तक नहीं ले जाया जा सकता है जो इसके कारण है। उनके द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के लिए उधारकर्ता पर जोर नहीं दिया, लेकिन निगम को निष्पक्षता के नाम पर हाथ और पैर नहीं छोड़ा जा सकता है। निष्पक्षता एक तरह से सड़क नहीं है, विशेष रूप से वर्तमान में एक जैसे मामलों में। "

(17) हरियाणा वित्तीय निगम के अनुसार, रुपये का ऋण। 90 लाख 20 मार्च, 1993 को दिया गया था। इसे 29 त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना था। वादी के अनुरोध पर, डिफ़ॉल्ट राशि को बकाया राशि के पुनर्निर्धारण के अनुसार भुगतान करने की अनुमति दी गई थी। वादी ने पुनर्निर्धारित राशि के भुगतान में चूक की। रुपये की कुल राशि में से। 174.88 लाख, देय ऋण समझौते के पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार, वादी ने केवल रु। 55.80 लाख और शेष राशि 19 सितंबर, 1997 से आगे की रुचि के कारण थी। हरियाणा वित्तीय निगम का निर्णय वादी की इकाई को संभालने का इस प्रकार असमान या अन्यायपूर्ण नहीं था। यह सार्वजनिक धन है जिसे औद्योगीकरण के लिए निगम के माध्यम से चैनल किया जा रहा है। यदि ऋण समय पर नहीं चुकाया जाता है, तो सार्वजनिक धन का कोई पुनर्चक्रण नहीं होगा और यदि सार्वजनिक धन का पुनर्चक्रण नहीं है, तो औद्योगिकीकरण के लिए कोई विकास नहीं होगा। सीखा जिला न्यायाधीश

ने देखा है कि वादी ने सूट दाखिल होने के बाद एक भी पाई का भुगतान नहीं किया है और दिए गए चेक को वापस ले लिया गया है। वादी ने दिसंबर, 1997 में इस सूट की स्थापना की। सूट की संस्था के बाद भी, रुचि को और आगे बढ़ाया गया।

(18) ऊपर दिए गए कारणों के लिए, इन संशोधनों की अनुमति है और नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा पारित किए गए आदेशों को अलग रखा गया है। वादी के पक्ष में दी गई अस्थायी निषेधाज्ञा खाली हो जाती है।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पारिंदर सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

जींद, हरियाणा